Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 15-12-2006

Participants : Kumar Shri Shailendra

>

Title: Need to set up a Committee to fix the fees for government and private educational institutes in the country.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण विाय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। पूरे देश में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा में, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो, अधिकतर शिक्षण संस्थाओं में मनमाने ढंग से फीस की वसूली हो रही है। सरकारी स्कूलों के बारे में मैं नहीं कहता, राज्य सरकारें इस बारे में बराबर पहल करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा थी कि उसे राज्य सरकार ने थोड़ा कम किया है। मेरी सदन से मांग है कि मनमाने ढंग से जो फीस की वसूली होती है, चाहे वह भवन निर्माण के नाम पर हो, विकास के नाम पर हो या सैन्ट्रली ए.सी. लगाने के नाम पर हो, तमाम ऐसे शुल्क अभिभावकों से लिये जाते हैं। खासकर यह भी देखा गया है कि कभी-कभी इन शिक्षण संस्थाओं में छः महीने या साल भर की फीस इकठ्ठी ली जाती है। हमारे देश में ऐसे बहुत अधिक परिवार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वे सारी फीस एकदम देने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए इस पर रोक लगाने के लिए सरकार एक विशेाज्ञ समिति गठित करे, ताकि वह प्रति साल यह मूल्यांकन करे कि सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक फीस का क्या निर्धारण हो, मेरी मांग है कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाए।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में वह सदन को कुछ आश्वासन दें तथा सरकार की एक कमेटी बनायें, ताकि वह साल दर साल जब नया सत्र शुरू हो तो उसका पुनर्मूल्यांकन करे कि कितनी फीस प्र ाइमरी, माध्यमिक, इंटर, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीज में ली जाए, कृपया सरकार यह सुनिश्चित करायें।